महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.
दूरभाष : 0135-2608125, फैक्स : 2608126.
ईमेल : ut-urrda@pmgsy.nic.in.
urrda@yahoo.com.

सख्याः 347 / आई04–21 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 2015 दिनांक 5 मई, 2016

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता, (गढवाल / कुमाँऊ)
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता,
   पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड।

विषयः– ऑडिट द्वारा उल्लेखित विभिन्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा किये गये ऑडिट एवं विभाग द्वारा कराये गये Internal Audit में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की कमियां दृष्टिगोचर हुई है। इस सम्बन्ध में कार्यक्रम हेतु जारी Guidelines, Bidding Document एवं Manuals में दिये गये प्राविधानो के अनुसार विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

1. **Performance Security & Security Deposit** :- Bidding Document के Instructions to Bidder Clause No. 30 एवं General Condition of Contract के Clause 46 के अनुसार अनुबन्ध करते समय अनुबन्ध की लागत की 2.5 प्रतिशत Performance Security जो Scheduled Commercial Bank की FDR अथवा Bank Guarantee के रूप में होगी, ली जानी है, तथा कार्य के रनिंग बिलो से 2.5 प्रतिशत Performance Security एवं 5 प्रतिशत Security Deposit की कटौती किये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार कार्य की समाप्ति पर 5 प्रतिशत Performance Security एवं 5 प्रतिशत Security Deposit कुल 10 प्रतिशत Security उपलब्ध होनी अनिवार्य है।
2. **Field laboratory –**
   Bidding Document की General condition of Contract के Clause 52.2(i) के अनुसार कार्य आरम्भ होने के 30 दिन के भीतर अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य स्थल पर लैब स्थापित किये जाने का प्राविधान है यदि अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्यस्थल पर निर्धारित समयावधि के भीतर लैब स्थापित नहीं की जाती है तो अनुबन्धित फर्म का यह कृत्य Breach of Contract होगा।
3. **Insurance**
   Bidding Document की General Condition of Contract के Clause 13 के अनुसार कार्य आरम्भ करने से पहले अनुबन्धित फर्म द्वारा अपने खर्च पर निम्न Loss or Damage हेतु Insurance करा कर उसके Certificate Employer को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने है।
   a) Loss of or damage to the Works, Plant and Material.
   b) Loss of or damage to Equipment.

c) Loss of or damage to property (other than the Works, Plant, Materials and Equipment) in connection with the Contract.

d) Personal injury or death.

यदि अनुबन्धित फर्म उक्त Insurance करा कर Policy Certificate ससमय प्रस्तुत नहीं करती है, तो clause 52.2(f) के अनुसार यह Breach of Contract होगा ।

4. **Advance Payment**

Bidding Document की General Condition of Contract के Clause 45 के अनुसार अनुबन्धित फर्म की मांग पर Scheduled Commercial Bank की Unconditional Bank Guarantee के विरूद्ध निम्न अग्रिम भुगतान किये जाने का प्राविधान है। Unconditional Bank Guarantee की लागत दिये जाने वाले अग्रिम की लागत के 110 प्रतिशत के बराबर होनी अनिवार्य है, जो अग्रिम के सापेक्ष किये गये भुगतान के अनुसार घटायी जा सकती है परन्तु इसकी अवधि अग्रिम भुगतान के repayment तक बनी रहनी आवश्यक है।

a) मोबिलाईजेशन अग्रिम, Initial Contract Price (अनुरक्षण की लागत को छोड़ कर) का अधिकतम 5 प्रतिशत बैंक गारंटी के विरूद्ध दिया जा सकता है।

b) इक्यूप्मेन्ट अग्रिम, खरीदे जाने वाले नये इक्यूप्मेन्ट की लागत का 90 प्रतिशत तक बैंक गारंटी के विरूद्ध दिया जा सकता है, परन्तु इसकी अधिकतम सीमा Initial Contract Price (अनुरक्षण की लागत को छोड़ कर) के 10 प्रतिशत के अन्तर्गत होनी आवश्यक है।

c) अनुबन्धित फर्म द्वारा लिये गये अग्रिम के सापेक्ष किये गये व्यय के बिल एवं अन्य Document, Employer को प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है।

d) जारी किये गये अग्रिम की वसूली अनुबन्धित फर्म के बीजको से मूल अनुबन्धित अवधि के भीतर अनुबन्ध के समय प्रस्तुत Completion Schedule की Percentage के अनुसार की जानी है। यदि अनुबन्धित फर्म द्वारा Completion Schedule के अनुसार कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है तो भी मूल Completion Schedule की Percentage के अनुसार ही अग्रिम की वसूली की जानी है। इसके अतिरिक्त यदि अनुबन्धित फर्म कार्य करने से Default कर जाती है तो अग्रिम की धनराशि की वसूली तत्समय के भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ की जायेगी।

e) **मोबिलाईजेशन एवं इक्यूप्मेन्ट अग्रिम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अग्रिम जैसे Material Advance, Advance to supplier आदि पूर्णतः प्रतिबन्धित है,** जबकि ऑडिट द्वारा अवगत कराया गया कि कई प्रकरणों में पी0आई0यू0 द्वारा Material Advance, Advance to supplier हेतु अग्रिम भुगतान किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में तत्काल वसूली की कार्यवाही की जाय तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

5. **Time Control**

General Condition of Contract के clause 26, 27 एवं 40 में समय से कार्य पूर्ण कराने हेतु निम्न प्राविधान है–

ठेकेदार Letter of Acceptance जारी होने के 15 दिन के भीतर अपना प्रोग्राम, जिसमें मुख्य रूप से कार्य करने हेतु समय सारणी, Equipment, मशीनरी, Key Personnel की list एवं Equipment के साथ Field Laboratory की location देंगे तथा Engineer in charge इन्हें verify करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 60 दिवस के interval पर ठेकेदार Actual progress का updated programme देंगे, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो

Engineer in charge रू0 2.00 लाख ठेकेदार के बीजक से withheld करेंगे। इस सम्बन्ध में Clause 26 में निम्नानुसार प्राविधान है–

(i) Programme

- Within the time stated in the Contract Data at S.N0. 17(a), the Contractor shall submitted to the Engineer for approval a programme showing the general methods, arrangements, order and timing for all activities in the Works, for the construction of works.
- The Contractor shall submit the list of equipment and machinery being brought to site , the list of key personnel being deployed, the list of machinery/ equipments being placed in the field laboratory and the location of field laboratory along with the programme. The Engineer shall cause these details to be verified at each appropriate stage of the programme.
- An update of the programme shall be a programme showing the actual progress achieved on each activity and the effect of the progress achieved on the timing of the remaining Works, including any changes to the sequence of activities.
- The contractor shall submit to the Engineer for approval an update Programme at intervals no longer than the period stated in the Contract Data at S.No. 17(b). If the Contractor does not submit an updated programme within this period stated, the Engineer may withhold this amount in the Contract Data at S.No 17(c) from the next payment certificate and continue to withhold this amount until the next payment after the date on which the overdue programme has been submitted.

(ii) Extension of the Intended Completion Date

ऑडिट द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश प्रकरणों में 0.05 प्रतिशत से 0.80 प्रतिशत तक Penalty लगा कर समय वृद्धि प्रदान की गयी है। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ऐसा प्राविधान नहीं है। योजना के अन्तर्गत सामान्यतः समय वृद्धि नहीं दी जानी है, केवल अपरिहार्य कारणों, जैसे 15 जून से 15 सितम्बर के अतिरिक्त अप्रत्याशित वर्षा (Unseasonal Rains), शरदकाल के अतिरिक्त बर्फबारी का होना, वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात समरेखण में आ रहे वृक्षों के पातन में निर्धारित अवधि से अधिक समय लगना, समरेखण विवाद, मा0 न्यायालय द्वारा कार्य रोकने के आदेश अथवा अतिरिक्त कार्य कराने पर समय वृद्धि प्रदत्त की जा सकती है। इस हेतु पूर्ण Supporting Information एवं Document प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं तथा समय वृद्धि बिना किसी Liquidated Damages के जितने दिन कार्य अवरूद्ध होता है, उतने दिनों की समय वृद्धि प्रदान की जा सकती है। इस हेतु रूप पत्र TE-1 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार के कारण कार्य delay होता है तो प्रति सप्ताह Initial Contract Price की 1 प्रतिशत लागत के बराबर Liquidated Damages के साथ समय वृद्धि प्रदत्त की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 7 सप्ताह हो सकती है। समय वृद्धि के सम्बन्ध में GCC के Clause 27 में निम्नानुसार प्राविधान है–

- The Employer on recommendation of the Engineer shall extend the Intended Completion Date if a Compensation Event occurs or a Variation is issued which makes it impossible for Completion to be achieved by the Intended completion Date without the contractor taking steps to accelerate the remaining Works, which would cause the Contractor to incur additional cost.

- The Employer on recommendation of the Engineer shall decide whether and by how much time to extend the intended completion date within 21 days of the Contractor asking the Engineer for a decision upon the effect of a Compensation Event or Variation and submitting full supporting information. If the Contractor has failed to cooperate in dealing with a delay, the delay by this failure shall not be considered in assessing the new Intended Completion Date.

(ii) Clause 40- Compensation Events

- The following shall be compensation Events unless they are caused by the Contractor:
  - **(a)** The Engineer orders a delay or delays exceeding a total of 30 days.
  - **(b)** The effects on the Contractor of any of the Employer's Risks.

- If a Compensation Event would prevent the works being completed before the intended Completion Date, the Intended Completion Date shall be extended. The Engineer shall recommend to the Employer whether and by how much the Intended Completion Date shall be extended. Final approval shall rest with the Employer.

6. **Recovery of Liquidated Damages**

Audit द्वारा अवगत कराया गया कि General Condition of Contract के clause 44 के अनुसार कार्य में देरी होने पर Liquidated Damages 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम Initial Contract Price का 10 प्रतिशत लगाया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा जांचे गये सभी प्रकरणों में Liquidated Damages, discretional rates से केवल 0.05 प्रतिशत से 0.80 प्रतिशत तक ही लगाया गया है। Liquidated Damages के सम्बन्ध में clause 44 में निम्नानुसार प्राविधान है–

- In the event of failure on part of the Contractor to achieve timely completion of the project, including any extension of time granted under clause 27, he shall, without prejudice to any other right or remedy available under the law to the Employer on account of such breach, pay as agreed liquidated damages to the Employer and not by way of penalty in a sum calculated at the rate per week or part thereof as stated in the Contract Data at S.N0. 20. For the period that the completion date is later then the intended Completion date, liquidated damages at the same rate shall be withheld if the Contractors fails to achieve the milestone prescribed in the Contract Data at S.N0. 20. However, in case the Contractor achieved the next milestone, the amount of the Liquidated Damages already withheld shall be restored to the Contractor by adjustment in the payment certificate. Both the Parties expressly agree that the total amount of Liquidated Damages shall not exceed 10 % of Initial Contract Price and that the Liquidated Damages payable by the Contractor by the mutually agreed genuine Pre-estimated loss and without the proof of actual damage likely to be suffered and incurred by the Employer, and the Employer is entitled to receive the same and are not by way of penalty.

The Employer may without prejudice to any other method of recovery, deduct the amount of such damages from any sum due, or to become due to the Contractor or from performance security any other dues from Government or Semi Government bodies within the state.

The payment or deduction of such damages shall not relieve the Contractor from his obligations to complete the works, or from any other of his duties, obligations or responsibilities under the Contract.

The Contractor shall use and continue to use his best endeavors to avoid or reduce further delay to the works, or any relevant stages.

- If the Intended Completion Date is extended after Liquidated Damages have been paid the engineer shall correct any such payment of liquidated damages by the Contractor by adjusting the next payment certificate.
- It is agreed by the Contractor that the decision of the Employer as to the Liquidated Damages payable by the Contractor under this clause shall be final and binding.

7. **Delay in Termination of Contracts**

Audit द्वारा अवगत कराया गया कि GCC के Clause 52 के अनुसार यदि ठेकेदार Engineer in charge के Authorization के बिना लगातार 28 दिन कार्य रोक देते है तो Employer को उसका अनुबन्ध निरस्त कर देना चाहिए, परन्तु कतिपय प्रकरणों में पी0आई0यू0 द्वारा एवं अनुबन्धों के निरस्तीकरण में अत्याधिक समय लगा दिया, जिस कारण समय से निर्णय न लिये जाने के कारण अवशेष कार्यों की लागत काफी बढ़ गयी तथा कार्यों को पूर्ण कराने में अतिरिक्त धनराशि वहन करनी पड़ी। Termination के सम्बन्ध में Clause 52 में निम्नानुसार प्राविधान है–

- The Employer may terminate the Contract if the Contractor caused a fundamental breach of the Contract.
- Fundamental breaches of the Contract shall include, but shall not be limited to, the following :
  (a) the Contractor stops work for 28 days when no stoppage of work is shown on the current Programme and the stoppage has not been authorized by the Engineer;
  (b) the contractor declared as bankrupt or goes into liquidation other than for approved reconstruction or amalgamation;
  (c) the Engineer gives notice that failure to correct a particular defect whether pertaining to construction work or pertaining to defects liability period is a fundamental breach of the Contract and the Contractor fails to correct it within a reasonable period of time determined by the Engineer;
  (d) the contractor does not maintain a security, which is required;
  (e) the contractor has delayed the completion of the works by the number of days for which the maximum amount of liquidated damages can be paid, as defined in clause 44.1;
  (f) the Contractor fails to provide insurance cover as required under clause 13;

(g) if the Contractor, in the judgment of the Employer, has engaged in the corrupt, fraudulent or coercive practice in competing for or in executing the Contract. For the purpose of this clause, "coercive practice" means the offering, giving, receiving, or soliciting of anything of value to influence the action of a public official in the procurement process or in Contract execution. "Fraudulent Practice" means a willful misrepresentation or omission of facts or submission of fake/forged documents in order to induce public official to act in reliance thereof, with the purpose of obtaining unjust advantage by or causing damage to justified interest of others and/or to influence the procurement process to the detriment of the Government interests. And, this includes collusive practice among Bidders (prior to or after bid submission) designed to establish bid process at artificial non-competition levels and to deprive the Employer of the benefits of free and open completion. "Coercive practice" means the act of obtaining something, compelling an action or influencing a decision through intimidation, threat or the use of force directly or indirectly, where potential or actual injury may befall upon a person, his /her reputation or property to influence their participation in the tendering process.

(h) if the Contractor has not completed at least three-eight of the value of construction work required to be completed after half of the completion period has elapsed;

(i) if the Contractor fails to set up a field laboratory with the prescribed equipment, within the period specified in the Contract data at S.N0 24;

(j) if the Contractor fails to deploy machinery and equipment or personnel as specified in the Contract data at the appropriate time; and

(k) if the Contractor fails to pay EPF/ESI contribution as required under prevailing laws;

(l) if the Contractor engages child labour in violation of prevailing laws;

(m) if the Contractor fails to ensure that there is no gender bias in engagement of labour and other employees and in payment of wages and he discriminate against female workers.

(n) Any other fundamental breaches as specified in the Contract Data.

- Notwithstanding the above, the Employer may terminate the contract for convenience.

- If the Contractor is terminated, the Contractor shall stop work immediately, make the site safe and secure, and leave the site as soon as reasonably possible.

8. **Refund of Security Deposit & Performance Security**

General Condition of Contract के clause 43 में, security deposit एवं performance security अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में यह प्राविधान है, कि संतोषजनक कार्य पूर्ण होने के पश्चात, security deposit की आधी धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी, एक चौथाई धनराशि कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष पश्चात तथा अवशेष एक चौथाई धनराशि कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष पश्चात इस शर्त के साथ अवमुक्त की जायेगी, कि कार्य पर जो भी defects, Engineer द्वारा ठेकेदार को बताये गये थे, वे सब संतोषजनक रूप से ठीक कर दिये गये हैं।

Performance security, जो Contract price के 5 प्रतिशत के बराबर होगी, सम्बन्धित ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण होने के पांच वर्ष पश्चात् (एवं स्टेज–1 कार्य में दो वर्ष पश्चात्) इस शर्त के साथ अवमुक्त की जायेगी, कि ठेकेदार द्वारा Routine Maintenance के कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये गये हैं।

यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा Routine Maintenance के कार्य नहीं किये जाते हैं तो Employer द्वारा Routine Maintenance के कार्य किसी अन्य source से करा लिये जायें तथा इन कार्यों को कराने में जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है वह धनराशि, उपलब्ध Performance security से अथवा ठेकेदार की उपलब्ध अन्य धनराशि से 20 प्रतिशत की Penalty के साथ कटौती कर ली जाये।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

5/5/16

(ए0 के0 दिनकर)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

5/5/16

मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

FORMAT (TE-I)

Application for Extension of Time

1- (a) Name of Contractor .....
   (b) Agreement No. & Date .....
2- Date of Receipt of application from contractor .....
3- Work done up to date of application by contractor, in terms of Amount Rs....., in terms of %.....
4- Work done up to time, in terms of Amount Rs....., in Terms of %.....
5- Date up to which Extension already sanctioned, if any .....
   (i) 1st Extension up to Vide letter No.
   (ii) 2nd Extension up to Vide letter No.
6- Work done up to last sanctioned Extension, in terms of Amount Rs....., in terms of %.....
7- Details of recommendation for which extension is recommended with supporting documents.

Sl. No.	Nature of hindrance	Date of start of hindrance	Date up to which it is likely to last	Over lapping dates if any with reference to other items	Net period in days which can be considered for extension	Remarks, if any

Total ..... Days or up to .....

8- (a) Value of extra items if any (Non BOQ amount) Rs .....
   (b) Proportionate Period of Extension of time for extra works based on tendered cost .....
9- Actual date of completion in the works has been completed- .....
10- Date up to which extension is recommended for Para 7 & 8-.....
11- Remarks and recommended by Engineer in charge, stating whether Liquidated Damages imposed due to slow progress, if so give details.

Engineer in charge